17-35 hrs.

MOTION *RE.* CONTEMPT OF HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER : As the House is aware, at about 12-25 Hours to-day, a visitor calling himself Dev Dutt Sharma threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House and shouted slogans. The Watch and Ward Officer took him into custody immediately and interrogated him. The visitor has made a statement, and has expressed regret for his action.

I bring this to the notice of the House for such action as it may deem fit.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : I beg to move:

"This House resolves that the person calling himself Dev Dutt Sharma, son of Shri Bishamber Dayal Sharma, who threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House and shouted slogans at about 12-25 hours to-day, and whom the Watch & Ward Officer took into custody immediately, has committed a grave offence and is guilty of of the contempt of this House.

This House further resolves that he be kept in the custody of the Watch and Ward Officer till the rising of the House to-day, and, thereafter, released with a stren warning".

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"This House resolves that the person calling himself Dev Dutt Sharma, son of Shri Bishamber Dayal Sharma, who threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House and shouted slogans at about 12-25 hours to-day and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, has commited a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be kept in the custody of the Watch and Ward Officer till the rising of the House to-day, and, thereafter, released with a stern warning".

The motion was adopted.

17-40 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS 1982-83—(*Contd.*)

MINISTRY OF LABOUR

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will take up discussion and voting on the Demands Nos. 65 and 66 relating to the Ministry of Labour for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial numbers of cut motions to be moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1983, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 65 and 66 relating to the 'Ministry of Labour'."

*Moved with the recommendation of the President.

Demands for Grants, 1982-83, in respect of the Ministry of Labour submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16th March, 1982		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
Ministry of Labour:					
65.	Ministry of Labour	18,52,000	—	92,62,000	—
66.	Labour & Employment	12,10,32,000	78,000	60,51,58,000	3,88,000

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri N. E. Horo.

SHRI N. E. HORO (Khunti): I have not come prepared. I do not know about it. I want to speak next time.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Pius Tirkey.

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurdwar): Just now I had spoken. I will speak next time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bindeshwari Dubey.

श्री बिन्देश्वरी दुबे (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

सदन को मालूम है कि पिछले दो वर्षों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष औद्योगिक प्रतिष्ठानों में और खास कर बुनियादी उद्योगों में जो काफी उत्साहवृद्धक वृद्धि हुई है, उस से जाहिर है कि औद्योगिक संबंध काफी सुधरे हैं और बिना औद्योगिक संबंधों के सुधार के ऐसा हो पाना संभव नहीं था वैसे एक निरन्तर कोशिश औद्योगिक संबंधों को बिगाड़ने की कुछ खास ट्रेड यूनियन सैन्टर्स और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा जारी है। उस के बावजूद हाल में कुछ ऐसी बातें उजागर हो कर सामने आई हैं, जिनसे स्पष्ट हो गया है कि अपने देश का श्रमिक वर्ग देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है और वह सामान्यता कामबन्दी करना नहीं चाहता या किसी दल विशेष के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह हड़ताल में जाना नहीं चाहता और अगर उस की ग्रीवासेज को दूर करने के लिए, उस की वाजिब शिकायतों को दूर करने के लिए उचित प्रयास जारी रहे, तो औद्योगिक शान्ति बनाए रखने में वह विश्वास करता है तथापि पिछली 19 जनवरी को प्रतिपक्ष के राजनीतिक दलों और उन से संबंधित ट्रेड यूनियन सैन्टर्स ने जो भारत बंद का आह्वान किया था और उन्होंने इस बात की पुरजोर कोशिश की थी कि जितने भी सरकारी सेवा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, यातायात से संबंधित कर्मचारी हैं, विद्युत केन्द्रों से संबंधित कर्मचारी हैं, कोयला, स्टील और विभिन्न उद्योगों से संबंधित कर्मचारी हैं, वे देश के सारे काम-

काज को ठप्प कर दें लेकिन उन के इस आह्वान को नजरान्दाज कर के देश के श्रमिकों ने, देश के कामकाज को, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कामकाज को यथावत् कायम रखा उस से कुछ बातें उभर कर ऊपर आई हैं। एक तो यह है कि देश के श्रमिकों ने देशभक्ति का परिचय दिया, अपनी समझदारी का परिचय दिया और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके नेतृत्व में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया।

दूसरी बात जो उजागर हुई वह यह है लोग जो अक्सर श्रमिकों में अपनी लोकप्रियता, अपने संगठन, अपनी शक्ति का बड़ा ढोल पीटते रहे, उनकी क्या स्थिति है यह बात स्पष्ट हो गयी। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि मजदूरों के प्रति उनकी नीयत क्या थी। उन्होंने श्रमिकों की कुछ मांगे उठायी थीं कि अर्शेशल कमोडिटीज का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिये से वितरण होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी मांगे उठायी थीं। श्रम मन्त्री ने उनसे आग्रह किया कि वे उनकी सारी मांगों पर बात करना चाहते हैं। मंत्री महोदय के बार-बार आग्रह ने उनको बेनकाब कर दिया क्योंकि उन्होंने यह प्रीकंडीशन रखी कि जब तक एस्मा वापिस नहीं लिया जाएगा तब तक वे बात नहीं करेंगे। अगर मजदूरों के प्रति उनमें वफादारी होती, उनकी मांगों की पूर्ति के लिये इच्छा होती तो वे श्रम मंत्री के आग्रह को स्वीकार करते और उनसे बातचीत करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

देश में इसके बारे में प्रतिक्रिया है। उन लोगों ने भी इसके सम्बन्ध में बड़ा जोर शोर से कहा है कि मजदूरों के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। किन्तु जब मजदूरों ने उन लोगों की प्रीकण्डीशन की बात को देखा तो उन्होंने ठीक किया। जितने भी हमारे विभिन्न जरूरी उद्योग हैं, स्टील, सीमेंट, कोयला, फर्टिलाइजर और दूसरे उद्योग उनमें 80 से 85 प्रतिशत लोग काम पर आये। उनमें उस रोज न केवल उत्पादन शतप्रतिशत हुआ बल्कि उससे भी अधिक हुआ। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि एस्मा के प्रति मज़दूरों का एक तरह से जनमत संग्रह था। उन्होंने इन्दिरा जी और उनकी सरकार में विश्वास किया कि यह एस्मा मज़दूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं है बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो देश में चाओटिक कंडीशंस पैदा करना चाहते हैं जो विघटनकारी तत्व हैं। एक तरह से मज़दूरों का यह एक राजनीतिक फैसला था।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कहने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने जबरी मज़दूरों को काम पर घुसाया। मज़दूरों को पुलिस वाले उनके घरों से, क्वार्टरों से पकड़ कर लाए, वे अपने मन से काम पर नहीं आये। यह भी कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ है यह सरकार का पिट्ठु है। मज़दूरों का विश्वासपात्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मज़दूर संघ ही मज़दूरों का एकमात्र विश्वासपात्र संघ है। कभी-कभी बातें होती हैं तो सुन कर ऐसा लगता है कि स्थिति खराब होती जा रही है। एक हमारे मित्र ने बड़े ज़ोरों से शेर कहा है। वह शेर बहुत अच्छा नहीं है पर वह मज़दूरों के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को अवश्य दर्शाता है—

बहुत शोर सुनते थे कि हाथी की दुम है।
जब नज़दीक से देखा तो रस्सी बंधी थी॥

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

इन्होंने श्रमिकों के लिए अब तक जो किया वह 19 तारीख के नतीजे से जाहिर हो गया। 19 तारीख का फैसला मजदूरों का फैसला था, देश की श्रमिक जमात का फैसला था। सरकार अब तक ऐसे ही उन नेताओं के दबाव में आती रही। वैसे लोगों से जो इस देश में काम-काज को चालू रखना चाहते हैं जो देश के प्रति वफादार हैं, श्रमिकों के प्रति वफादार हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिन्दा रखना चाहते हैं और वैसे लोगों को जो औद्योगिक सम्बन्धों को केआटिक बनाना चाहते हैं, देश में केआटिक कंडीशन पैदा करना चाहते हैं, देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको सरकार इक्वेट ही नहीं करती, बल्कि उनको कई मामलों में प्रिफरेंसेस मिलता रहा है विभिन्न ज्वाइंट फोरम्स में, विभिन्न ट्रिपाटाईट बाडीज में उन्हें बराबरी का हक मिला है। बराबरी का हक पाने का वे दावा करते हैं और पूववर्ती सरकार ने बराबरी का उन्हें हक दिया भी। इतना ही नहीं जनता पार्टी के शासन काल में एक अजीब बात हुई। पहले 4 ट्रेड यूनियन्स को केन्द्र सरकार मान्यता देती थी, जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 11 ट्रेड यूनियन्स को मान्यता दे दी। एक तरफ तो मजदूरों की एकता की बात कही, उन्होंने कहा कि मल्टीप्लीसिटी आफ ट्रेड यूनियन्स ही सारी बीमारी की जड़ है, इनको समाप्त करना चाहिए और इंटेग्रेशन की बात कही और सारा प्रोसेस डिसइंटेग्रेशन का किया, मजदूरों की एकता को तोड़ने की कोशिश की। सेन्टर ने तो 11 ट्रेड यूनियन्स को रिकगनाइज किया और स्टेट्स में तो और भी बहुत कुछ हुआ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा जी के शासन की अवधि काल में औद्योगिक सम्बन्ध सुधरे हैं। यह बात कोई मैं नहीं कहता। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहता। आंकड़े बोलते हैं कि पिछले दो सालों में मैन डेज का लासेस जनता पार्टी के शासन काल की तुलना में कितना कम हुआ है। 19 जनवरी के नतीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब श्रमिक वर्ग सामान्यतः हड़ताल नहीं करना चाहता, कामबन्दी करना नहीं चाहता देश के प्रति वफादारी निभाना चाहता है और वह चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी समस्याएं सुलझाई जाएं तो ऐसी हालत में सरकार की जवाबदेही श्रमिकों के प्रति बढ़ जाती है खासतौर पर श्रम विभाग की जवाबदेही और बढ़ जाती है और इस बात की आवश्यकता है कि श्रम-विभाग कस्टीट्यूशनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत करे। श्रम-विभाग उन उपायों को ढूंढे, जिनके माध्यम से मजदूरों के ग्रिवांसेस को तेज गति से सुलझाया जा सके और उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि एक ऐसी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी डवलप करे जो इस काम को कारगर ढंग से कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामले में सब सरकारों में समानता रही है। क्षमा करेंगे मेरे वर्तमान श्रम मंत्री महोदय। एक बात सब बोलते रहे हैं कि हम एक कंप्रिहेंसिव लेबर लाज ला रहे हैं और अब तक जितनी भी सरकारें आईं, सबने यह कहा पर किया किसी ने भी नहीं। दूसरी बात यह कि जितनी भी कमेटियां बनाई गई, ट्रिपाटाईट बाडीज बनाई, कमीशन बनाए गये या जितनी भी कान्फ्रेंसेस हुई, उन सब की सिफारिशें समानरूप से हर बार श्रम विभाग की अलमारियों में संजोकर रख दी गयीं। नेशनल कमीशन आफ लेबर ने 1969 में अपनी सिफारिशें दी थीं और उसने काफी

कारगर सुझाव दिए थे। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बनाने की बात की थी और कन्सिलियेशन बोर्ड को क्वासी ज्युडिशियल बाडीज बनाने की बात कही थी जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मजदूरों के ग्रिवांसेस को स्पीडली अटेंड किया जा सकता है और न्यायपूर्वक समाधान निकाला जा सकता है।

आज क्या स्थिति है? आर्बिट्रेशन एक सर्वमान्य सिद्धांत है, मजदूरों के ग्रिवांसेस को सैटल करने का। हम चाहते हैं कि श्रम-विभाग मिडिएशन सर्विसेस को अधिकाधिक स्ट्रेंगदेन करे और उसको और कारगर बनाए और वालेंटरी आर्बिट्रेशन को प्रोत्साहन दे, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशानी कहां है? प्राइवेट सैक्टर की तो बात छोड़ ही दीजिए, लिटिगेशन में जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो जाए तब भी मजदूरों के ग्रिवांसेस को, उनकी मांगों को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक सैक्टर्स और अण्डरटेकिंग्स में क्या हो रहा है?

नेशनल लेवल पर एक फैसला हुआ था कि पब्लिक सेक्टर्स अण्डरटेकिंग्स लिटिगेशन नहीं बढ़ायेंगी और ट्रिब्यूनल के फैसलों को स्वीकार कर लेंगी, आर्बिट्रेशन के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी पर आज स्थिति यह है कि श्रम विभाग की जो कंसीलिएशन मशीनरी है, डिस्प्यूट में अगर मतभेद हो जाता है, कन्सीलिएशन फेल्युअर की स्थिति में आ जाती है तो वे दोनों पक्षों को आफर करते हैं कि वे आर्बिट्रेशन स्वीकार करें? मजदूर संगठन आर्बिट्रेशन स्वीकार करता है इनवेरिएबली इन एब्रीकैस, 95 परसेंट कैसिस में लेकिन पब्लिक सैक्टर मैनेजमेंट एक भी केस में आर्बिट्रेशन नहीं मानता है। अगर कभी मान भी लेता है तो उसके फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करता। आप इन्कार नहीं कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल एक डायलेटरी प्रासैस है। एडजुडिकेशन का प्रासेस कितना लम्बा है, कितना उसमें डिलै होता है इसको भी सभी जानते हैं। एक मजदूर अगर डिसमिस हो जाता है या मजदूरों की कुछ शिकायतें उठती हैं और वे साल्व नहीं होती हैं तो मामला ट्रिब्यूनल में जाता है। सालों साल वहां लग जाते हैं। अब आप डिसमिस्ड कर्मचारी की प्लाइट को देखें। उसके केस का ट्रिब्यूनल में फैसला होते-होते चार पांच साल लग जाते हैं। उसके बाद भी पब्लिक सैक्टर एम्प्लायर है वह हाई कोर्ट में चला जाता है। दर्जनों केस मेरे सामने हैं। हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। आप देखें की क्या मजदूर के पास इतने साधन हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक में अपने केस को डिफेंड कर सके? श्रम विभाग को इसके लिए कुछ कारगर उपाय ढूंढने होंगे। मैं मानता हूँ कि आर्बिट्रेशन के मामले में कम्पलशन होनी चाहिए। मजबूर किया जाना चाहिए कि आर्बिट्रेशन को माना जाए, पंचायत का फैसला हो जाए तो उसको मान लिया जाए ताकि मजदूर को राहत मिल सके।

वेज फिक्सेशन के बारे में भी गवर्नमेंट की एक पालिसी होनी चाहिए। यह कहा जाता है कि आर्गेनाइज्ड सैक्टर के श्रमिकों ने अपनी बारगेनिंग पावर की शक्ति से अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि देश में ऐसे भी कोटि-कोटि लोग हैं जो उनके नीचे के स्तर के हैं और उनको कुछ नहीं मिला है। एक बात की जानकारी श्रम विभाग को होगी कि आज अर्गेनाइज्ड सैक्टर में भी एक प्रकार का हैंफ हैजर्ड ग्रोथ हो रहा है, इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। माइनिंग इण्डस्ट्री में डी मैगनेसाइट में, लाइम में, मैंगनीज में, माइका में,

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

डोलोमाइट आदि उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी स्थिति को आप देखें। क्या शोषण उनका हो रहा है इसको आप गहराई से देखें और इसकी छानबीन करें। उनको जो वेज मिलती है वह सबसिस्टेंस लेवेल के भी नीचे है। जो कुछ न्यूनतम मजदूरी के नाम पर मिलता है वह सब-सिस्टेंस लेवेल के भी नीचे होता है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक फेयर वेज कमेटी बनी थी जिस में डिस्टिंगुइशड परसनैलिटीज़ थीं। उन्होंने युनैनिमस रिपोर्ट दी थी कि लोएस्ट पैड वर्कर जो हैं उसकी वेज का सेंट परसेंट प्रोटैक्शन होना चाहिये और प्राइस इंनक्रीज़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिये। उसने कहा था कि सेंट परसेंट प्रोटैक्शन देने के लिए न्यूट्रलाइजैशन की कोई प्रणाली निकाली जाए। लेकिन यह चीज़ हुई नहीं। जिस गति से कीमतें बढ़ रही है उसकी वेज इरोड होती जाती है। 1951 में जो मजदूरी न्यूनतम उनको मिलती थी—बहुत सी ट्रेड्ज़ का मैं हवाला दे सकता हूँ—वह न्यूनतम मजदूरी भी आज उनकी प्रोटैक्टिड नहीं है, वह इरोड हो गई है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। आप कॉट्रैक्ट लेबर को लें, रोड बिल्डिंग को लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को लें, उनमें काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है। उनकी क्या हालत है इसको आप देखें। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इन सब चीज़ को गहराई से देखना चाहिए।

फ्रिंज बैनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी के मामले में यूनिफार्मिटी होनी चाहिये, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसका इंटैग्रेशन भी होना चाहिये, इंटेग्रेटिड पालिसी होनी चाहिये। कोल माइंज प्राविडेंट फंड को आप देखें। जब से कोयला खदान उद्योग का नैशनलाइजेशन हो गया है तब से ही हम कहते रहे हैं कि कोल माइंज प्राविडेंड फंड को आप एम्प्लायर को दे दें, उनसे मजदूर लड़ कर अपना जमा पैसा ठीक समय पर ले लिया करेंगे। आज छः छः महीने तक रिटायर होने के बाद उनका जमा उनको नहीं मिलता है, साल-साल भर नहीं मिलता है। सारे विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मजदूरों को अपना जमा पैसा वापस पाने में अपने जमा पैसे की भारी रकम विभागीय कर्मचारियों को दे देना पड़ती है। उस पैसे का प्रौपर इन्वैस्टमेंट भी नहीं होता है। कम्पलसरी डिपोजिट के लिये पैसा काटने को सरकार सदा तैयार रहती है। प्रौवीडेंट फंड के पैसे को ऐसी जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट करें कि जिससे जहां ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा मिल सके। यह भी सोचा जाना चाहिए कि लेबर लाज़ को कैसे इफैक्टिव बनाया जाय, उनका इमप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। लेबर लाज़ इतने पुराने पड़ गये हैं चाहे इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट हो या अन्य ऐक्ट हो, उनमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। आप देखें माइन्स ऐक्ट अमेंडमेंट बिल 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ और वह एक जोइंट सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द हो गया। सरकारें बदलती गयीं, रवीन्द्र वर्मा जी ने श्रम मंत्री के रूप में जनता सरकार में थे तो उन्होंने उसको रिवाइव भी किया। लेकिन फिर खत्म हो गया। उसमें अच्छे और कारगर प्रौवीजन्स थे, जैसे छुट्टी का वर्कर्स इस्पेक्टर्स रखने का। सेफ़टी के भी प्रौवीज़न में भी सुधार की बातें थीं। पिछले वर्षों में माईनिंग इंडस्ट्री में ऐक्सीडेंट्स में वृद्धि हुई है और कारण यह है कि नेशनेलाइज़ेशन के बाद से इंस्पेक्टोरेट की ग्रिप कमजोर पड़ती जा रही है। एक छोटी सी मिसाल दूं एक नेशनल काउन्सिल आफ सेफ्टी इन माइन्स आर्गेनाइज़ेशन है,

ट्राइपटाईट बोडी है। ऐसा समझा गया कि जो इंस्पेक्टोरेट है वह माइन्स में सेफ्टी कांसेशनैस लाने का काम ठीक से नहीं कर पाती। इसके लिये ट्राइपटाईट बौडी बनी। उसके लिये फंड्स देती रहती है। कोलमाइन्स वैलफेअर आर्गनाइजेशन अब यह एनर्जी में चली गई तो कहते हैं कि एनर्जी मिनिस्ट्री का यह काम थोड़े ही है। लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए अलग से फंड दे। अब यह झगड़ा कि श्रम विभाग फंड दे या एनर्जी विभाग दे, इस चक्कर में काम ठप पड़ा है। कोल विभाग को उत्पादन चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिये कोई चिन्ता नहीं है। फंढ कौन दे इसको लेकर झगड़ा है। मैंने श्रम मंत्री से शिकायत की उन्होंने तुरन्त कार्यवाही भी की। श्रमिक सम्बन्धों का विषय एक बड़ा ही सैन्सिटिव विषय है। आज श्रम विभाग की स्थिति एक फायर ब्रिगेड जैसी हो गई है। आग लगी तो दमकल दौड़ा। कोई कंटिन्युअस थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है कि किन किन कारणों से इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिगड़ते हैं, उनकी जांच करें और दूर करने का प्रयास निरन्तर जारी रहे। इस बात के लिये कोई सतर्कता नहीं है। श्रम विभाग का जो महत्व स्वतंत्रता के बाद अपने देश में था वह क्रमशः कम होता जा रहा है। यह श्रमिक जमात के लिये दुख की बात है। सब से ज्यादा उस महत्व को कम करने में सरकार की ऐमप्लाइंग मिनिस्ट्रीज का हाथ है। सब से ज्यादा अगर कोई वायलेशन करते हैं तो सरकारी प्रतिष्ठान करते हैं। इनडिफरेंट ऐटीट्यूड उनका है। श्रम विभाग के बारे में, सब से ज्यादा श्रम विभाग को अगर नजरंदाज करते हैं तो वही करते हैं। श्रमिक जमात के लोग पूछते हैं कि श्रम विभाग में राज्य मंत्री ही क्यों? क्या कम महत्व का है यह मंत्रालय? क्या यहां कैबिनट स्तर का मंत्री नहीं होना चाहिये?

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : He is a strong man, stronger than a Cabinet Minister. Cabinet status does not matter at all.

श्री बिन्देश्वरी दुबे : हमारे वर्तमान राज्य मन्त्री योग्य हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं तो श्रम विभाग के महत्व की दृष्टि से इस बात को कह रहा था.....

18 Hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you want to conclude now or to take some more time ?

SHRI BINDESHWARI DUBEY : If you can kindly permit me, I will take some more time.

MR. DEPUTY SPEAKER : Then, you can continue on Wednesday.

SHRI R.L.P. VERMA (Kadarma): I beg to move:—

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Failure to set up Mica Wave Board. (6)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to take positive action against the officers of public sector undertakings responsible for ignoring the original inhabitants of Chhota Nagpur in the matter of employment. (7)].

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Shri R. L. P. Verma]

[Need to recognise the labour unions by secret ballot. (93)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to verify the strength of all trade unions for healthy growth of trade unionism. (94)).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to safeguard the casual labourers in various private industries against exploitation. (95))]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to cut down the lengthy process of arbitration in industrial disputes and other cases under labour laws and rules. (96)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide essential commodities through the subsidised labour cooperative societies to the workers. (97)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to regularise workers engaged in beedi industry. (98)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to stop retrenchment of workers and casual appointees. (99)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide residential accomodation to atleast 80 per cent of employees working in public sector undertakings. (100)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to revise pay-scales of labourers working in coal, iron and mica mines. (101).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to make adequate arrangements for free exhibition of patriotic and nationalist films for increasing production by arousing national interest in the labourers. (102)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to popularise the slogan "Work in national interest and full wages for the work". (103)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to impose ban on political appointments in public undertakings. (104)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to raise the status of workers by providing free technical education to their children. (105)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced Rs. 100/-".

[Need to give encouragement to nationalist workers and to keep a secret watch on the activities of workers' organisation working on foreign guidelines. (106)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give recognition to IISCO Sharimik Sangh (Bhartiya Mazdoor Sangh), at Kulti and Burnpur. (107)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide adequate funds for purchase of educative and technical films for workers. (108)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to ensure timely payment of contributions to Provident Fund and damages under workers' deposit linked insurance scheme. (109)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to rehabilitate and provide employment opportunities to bonded labourers in Chhota-Nagpur. (110)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide modern amenities of life in Tribal and Harijan labour colonies. (111)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to implement rural artisan training programme and set up model industrial training institutes on mass scale. (112)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give proper guidance to women by giving them vocational training. (113)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to form welfare organisations and anti-exploitation task-force for agricultural labourers, contract labourers and unorganised rural labourers. (114)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to appoint a special study team to ensure strict enforcement of Minimum Wages Act. (115)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-"

[Need for modernisation and expansion of rescue services in mica and coal mines. (116)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to allot small plots of land to the permanent tea workers in Assam. (117)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check exploitation of casual labourers in the industrial areas of Delhi, Faridabad, and

[Shri R. L. P. Verma]

NOIDA and Ghaziabad where their services are terminated after 3 months and are reappointed again after a break to keep them temporary. (118)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to impress upon the employers to issue indentity cards or employment certificates to all workers. (119)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to close down private manpower export agencies which are exploiting and cheating the innocent job seekers (120).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to conduct a high level inquiry into the amassing of crores of rupees illegally by bogus labour agencies by deceiving thousands of workers of Kerala, Bihar and U.P.. on the pretext of arranging employment in and air passage to gulf countries. (121)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check malpractices in employment exchanges. (122)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check partiality in employment exchanges in forwarding names of registered persons for employment instead of following the rule of priority. (123)]

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move:—

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to meet the reasonable demands of public sector labour unions particularly in regard to parity of wages. (32)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to formulate and implement unemployment insurance scheme. (33)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide free legal assistance to workers to fight their cases in labour courts. (34)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide quarters to workers with the assistance of employer. (35)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give proper medical aid to labourers in workshops and plantations. (36)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give more facilities for apprentice training to the youths to get jobs and to increase production. (37)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to bring forward pension schemes (including family pensions) for all classes of labourers through L.I.C. or other organisation. (38)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide work on need basis. (39)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to have better understanding with workers regarding the introduction of computers (40)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give essential commodities at subsidised rates to workers instead of D.A. (41)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give more education facilities to the children of labourers particularly working in plantations and mines. (42)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give equal wage for equal work. (43)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check malpractices in recruitment of workers. (44)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide better maternity benefits to women workers. (45)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide transport facilities to all workers. (46)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to tone up the working of employment exchanges. (47)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to bring about coordination between different employment agencies. (48)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide vocational and the technical training to children of craftsmen particularly those engaged in hereditary and traditional craft. (49)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to settle labour disputes without delay. (50)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to link wages with production. (51)]

[Shri T. R. Shamanna]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to bring forward legislation to provide for management of trade unions by labourers only without interference of outsiders. (52)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide better safety measures in mining industries. (53)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to have more tripartite labour conferences at District level, State level and National level to bring about better cooperation and understanding between labour and employers. (54)]

SHRI K.A. RAJAN (Trichur): I beg to move:—

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1".

[Failure to check discrimination in according recognition to trade unions run by Opposition Parties. (55)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to ensure recognition of unions by ballot. (56)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to introduce a uniform labour policy for all workers throughout the country. (57)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to introduce uniform pay scales for the workers in all public undertakings. (59)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to implement labour laws effectively. (60)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to safeguard the trade union rights. (61)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to abolish contract labour system. (62)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to check mounting unemployment in the country. (63)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to enact suitable legislation to ameliorate the lot of agricultural labour. (64)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to give unemployment allowance to the jobless. (65)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to regularise the services of casual labourers working for more than one year. (66)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to implement the Minimum Wages Act for agricultural labours in the country. (67)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to abolish bonded labour system and implement rehabilitation scheme for bonded labourers. (68)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment be reduced by Rs. 100/-".

[Need to expedite formation of manpower Expert Corporation to curb the malpractices of the recruiting agents. (69)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1/-".

[Failure to introduce equal pay for equal work policy throughout the country. (58)]

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur): I beg to move:—

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check malpractices in employment exchanges. (132)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check partiality in employment exchanges in forwarding names of registered persons for employment instead of following the rule of priority. (133)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to conduct a high level inquiry into amassing the huge fortunes illegally by bogus labour agencies by delivering thousands of workers of Kerala, Bihar and U.P. on the pretext of arranging employment in and air passage to Gulf countries. (134)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to initiate workers' participation in management of industries. (135)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to ban giving Khesari dal as mode of payment to agricultural labour. (136)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide vocational training to woman in rural areas. (137)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to form welfare organisations and anti-exploitation task force for agriculture labourers, contract labourers and unorganised rural labourers. (138)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need for separate machinery to ensure strict enforcement of Minimum Wage Act. (139)]

[Prof. Ajit Kumar Mehta]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to check exploitation of casual labourers in the Industrial areas of Delhi, Faridabad, Noida and Ghaziabad. (140)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide identity cards of employment certificates to all workers. (141)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to close down private manpower export agencies which are exploiting and cheating innocent job seekers. (142)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide free entertainments to workers. (143)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide adequate funds for purchase of educative and technical films for workers. (144)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to ensure timely payment of contributions to Provident Fund and damages under workers' deposit linked insurance scheme. (145)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to rehabilitate and provide employment opportunities to bonded labourers. (146)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide necessary amenities of life in Tribal and Harijan labour colonies. (147)]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to introduce rural artisan training programme on mass scale. (148)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to enforce one man one job formula to solve unemployment problem in the country. (149)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to bring agricultural labour under the 'purview of the Central Government. (150)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to departmentalise workers by ending contract system. (151)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to grant recognition to trade unions through ballot. (152)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to enforce the rule of one industry one union. (153)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to prevent political appointments in public undertakings. (154)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide vocational and technical training to children of craftsmen particularly those engaged in hereditary and traditional crafts. (155)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to link wages with production. (156)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to prevent outside interference in management of trade unions. (157)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to arrange for more tripartite labour conferences at different levels to bring out better cooperation and understanding between labour and employers. (158)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to bring forward legislation to prevent outsiders from becoming secretaries of labour cooperatives. (159)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to ban child labour in all forms. (160)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to introduce old age pension scheme for all classes of labourers through L.I.C. and other organisations. (161)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to implement the principle of equal wage for equal work. (163)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to stop malpractices in recruitment of workers. (164)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by . 100/-".

[Need to provide better maternity benefits to women workers. (165)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide transport facility to workers from place of residence to place of work. (166)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Prof. Ajit Kumar Mehta]

[Need to enforce parity of wages among labourers. (167)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to formulate and implement unemployment insurance scheme. (168)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide free legal assistance to workers for cases in labour courts. (169)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide reasonable residential accommodation to all the workers. (170)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide proper medical aid to labourers in factories and plantations. (171)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to provide more facilities for apprentice training to aspiring youths. (172)]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100/-".

[Need to supply essential commodities at subsidised rates to workers in partial payment of D.A. (162)]

18.01 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 7, 1982/Chaitra 17, 1904 (Saka).